International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 29-01-2019; Accepted: 28-02-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 2; March 2019; Page No. 142-144

''प्राथमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या'' रूद्रप्रयाग जनपद के सन्दर्भ में

डॉ0 पूनम भूषण [1], डॉ0 आबिदा [2]

[1] असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राज0 स्ना0 महा0 अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड, भारत।

[2] असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राज0 स्ना0 महा0 अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड, भारत।

सारांश

प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव के विकास का मेरूदण्ड मानी गयी है। सभी कालों में शिक्षा व्यवस्था भिन्न – भिन्न रही है । प्राचीन काल में गुरूकुल प्रणाली से लेकर आज अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का माध्यम रही है। सरकारी आंकड़े बताते है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन लगातार घट रहा है बेसिक शिक्षा विभाग लाख कोशिशों के बावजूद नामांकन बढ़ाने में असफल रहा है। अध्ययन और सर्वे की मशहूर संस्था ''प्रथम'' की 2014 की सालाना शिक्षा रिर्पोट बताती है कि भले ही 96.7 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते है लेकिन 71 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जाते है। उत्तराखण्ड राज्य की वर्तमान स्थिति देखते है तो यहॉ लगभग 700 से अधिक स्कूल बन्द कर दिये गये है। प्रस्तुत अध्ययन में जनपद रूद्रप्रयाग के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या को जानने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द : शिक्षा मानव, गुरूकुल प्रणाली, शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक विद्यालयों, घटती छात्र संख्या।

प्रस्तावना

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि इस संसार में मानव ऐसा प्राणी है जिसकी सर्वविध उन्नति कृत्रिम है स्वभाविक नहीं है। शैशवकाल में बोलने, चलने आदि की क्रियाओं से लेकर बड़े होने तक सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने हेतु वह दूसरों पर निर्भर रहता है। समय–समय पर विभिन्न आयु में विविध माध्यमों और सामाजिक पर्यावरण के द्वारा व्यक्ति के गुणों का विकास होता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव के विकास का मेरूदण्ड मानी गयी है। सभी कालों में शिक्षा व्यवस्था भिन्न – भिन्न रही है। प्राचीन काल में गुरूकुल प्रणाली से लेकर आज अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का माध्यम रही है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलों की संस्था यूनेस्को के सांख्यिकी कार्यालय और ग्लोबल ऐजूकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के एक ताजा संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि भारत के लगभग 5 करोड़ बच्चे सेकेंडरी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते है। कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते है। अध्ययन और सर्वे की मशहूर संस्था ''प्रथम'' की 2014 की सालाना शिक्षा रिर्पोट बताती है कि भले ही 96.7 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते है लेकिन 71 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जाते है। ग्रामीण परिवेश के लोगों को शिक्षा देना और उन्हें शिक्षा के लिये तैयार करना शब्दों में सरल लगता है लेकिन व्यवहारिक रूप से यह कठिन कार्य है। सरकारी आंकड़े बताते है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन लगातार घट रहा है बेसिक शिक्षा विभाग लाख कोशिशों के बावजूद नामांकन बढ़ाने में असफल रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य की वर्तमान स्थिति देखते है तो यहॉ लगभग 700 से अधिक स्कूल बन्द कर दिये गये है। अकेले कुमाऊं में ही 396 प्राथमिक स्कूल बन्द किये गये है। राज्य गठन के बाद अब तक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या घटकर 50 प्रतिशत से कम रह गयी है घटती छात्र संख्या से परेशान शिक्षा विभाग ने 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में विलीनीकरण के आदेश दिये है दोनों मण्डलों गढ़वाल व कुमाऊं में 2430 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी छात्र संख्या 10 के कम है । गढ़वाल में 1365 कुमाऊं में 1065 विद्यालयों को आस–पास के विद्यालयों में विलीनीकृत किया गया है।

शोध के उद्देश्य

1. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला न दिलाने के कारणों को ज्ञात करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों विद्यालय में संसाधनों की स्थिति जानना।
3. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के वातावरण की जानकारी लेना।
4. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा का स्तर ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र

देश के उत्तरी भाग में स्थित नवगठित राज्य उत्तराखण्ड जिसकी स्थापना 9 नवम्बर 2000 को हुई, को देश का 27वां राज्य होने का गौरव प्राप्त है राज्य में 13 जनपद हैं जिसमें रूद्रप्रयाग जनपद को अध्ययन में शामिल किया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग की जनसंख्या 2,42,285 है। जिसमें 1,14,589 पुरूष और 1,27,696 महिलायें हैं। रूद्रप्रयाग का लिगांनुपात 1114 है। दूसरी तरफ रूद्रप्रयाग की साक्षरता दर 81.30 प्रतिशत है। जिसमें 93.90 प्रतिशत पुरूष और 70.35 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है।

जनपद रूद्रप्रयाग में 03 विकासखण्ड – अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ है। जनपद रूद्रप्रयाग में 545 सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में 260, विकासखण्ड जखोली में 173 व विकासखण्ड ऊखीमठ में 112 सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। जिसमें शोधकर्ताओं के द्वारा विकासखण्ड अगस्त्यमुनि को सुविधानुसार अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है।

शोध प्रविधि एवं उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकासखण्ड के 5 संकुलों के 1–1 प्राथमिक विद्यालय वाले गांव से प्रत्येक से 10–10 महिला व पुरूष का चयन विचारपूर्वक

सुविधानुसार निदर्शन पद्धति से किया गया है। इस प्रकार कुल 50 उत्तरदाताओं को न्याय दर्श के रूप में चुना गया है।

प्राथमिक सामग्री : संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार करके तथ्यों को संकलित किया गया है। इसके अलावा अवलोकन विधि एवं अनौपचारिक वार्तालाप का भी प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक सामग्री : संकलन हेतु पुस्तकों, सरकारी एवं गैरसरकारी स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़े समाचार–पत्र पत्रिकाओं, जनसंपर्क कार्यालय आदि से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन कर आवश्यक सामग्रियों का संकलन किया गया है। इंटरनेट भी सूचना के स्त्रोत के रूप में प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया गया है।

तथ्यों का संकलन वर्गीकरण, सारणीयन एवं वर्गीकरण

शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया है कि जनपद रूद्रप्रयाग में कितने प्राथमिक विद्यालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और कितने विद्यालय बन्द हो गये है, ताकि यह पता चल सके कि बच्चों की शिक्षा व शिक्षण कार्य इससे कितना प्रभावित हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार माता–पिता बच्चों के भविष्य को लेकर कितने सजग हैं इसका भी मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। यह जानने का भी प्रयास किया गया है कि विद्यालयों में किन– किन संसाधनों की कमी है और विद्यालयों का वातावरण कैसा है। यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि शिक्षक अपना कार्य समय पर कर रहे हैं कि नही। क्यों लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं। उन कारणों को ढूंढने का प्रयास भी किया गया है कि सरकार के अनेकों प्रयासों व जागरूकता अभियानों के बावजूद और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नयी शिक्षा व्यवस्था लागू करने के बाद भी सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या क्यों घट रही है यही शोध का उद्देश्य है।

रूद्रप्रयाग जनपद में सरकारी विद्यालयों की समस्याओं को जानने के लिये प्रयास किये गये है।

तालिका क्रमांक 1: सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिलाने का कारण

क्र0सं0	दाखिला नहीं दिलाने का कारण	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षण कार्य से असन्तुष्टि	28	56
2	उचित वातावरण न होना	8	16
3	संसाधनों की कमी	5	10
4	शिक्षकों की कमी होना	9	18
		50	100

प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को अभिभावक दाखिला नही दिलाना चाहते, इसके क्या कारण है। 56 प्रतिशत अभिभावक शिक्षण कार्य से असन्तुष्ट है। 16 प्रतिशत उत्तरादाताओं के अनुसार विद्यालय में उचित वातावरण नहीं है, 10 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार विद्यालय में संसाधनों की कमी है तथा 18 प्रतिशत के अनुसार शिक्षकों की कमी है।

तालिका क्रमांक 2: शिक्षकों की कमी सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	शिक्षकों की कमी है।	संख्या	प्रतिशत
1	हां	22	44
2	नहीं	28	56
	योग	50	100

प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है या नही। सूचनादाताओं के अनुसार 44 प्रतिशत मानते है कि शिक्षकों की कमी है तथा 56 प्रतिशत के अनुसार उनके यहां के विद्यालय में शिक्षकों की कमी नही रहती है।

तालिका क्रमांक 3: विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति

क्र0सं0	शिक्षक नियमित उपस्थित रहते है।	संख्या	प्रतिशत
1	हां	39	78
2	नहीं	11	22
	योग	50	100

प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचनादाताओं से ज्ञात होता है कि 78 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय में नियमित उपस्थित रहते है। 22 प्रतिशत शिक्षक नियमित उपस्थित नही रहते हैं।

तालिका क्रमांक 4: विद्यालय में संसाधनों की कमी के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	विद्यालय में संसाधन की कमी	संख्या	प्रतिशत
1	बैठने के लिए चटाई	10	20
2	पीन का पानी	11	22
3	विद्यालय भवन	09	18
4	शौचालय	15	30
5	सभी	05	10
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात है कि 20 प्रतिशत विद्यालयों में बैठने की चटाई की समस्या है। 22 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की, 18 प्रतिशत में उचित विद्यालय भवन, 30 प्रतिशत के यहां शौचालय की सुविधा नही है। 10 प्रतिशत के अनुसार विद्यालयों में सभी सुविधाएं लगभग सही स्थिति में उपलब्ध नही है।

तालिका क्रमांक 5: विद्यालय के शैक्षिक स्तर के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	शैक्षिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	17	34
2	थोड़ा बहुत अच्छा	33	66
3	अच्छा नही	–	–
4	बिल्कुल नही	–	–
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 34 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि सरकारी विद्यालय का शैक्षिक स्तर अच्छा है तथा 66 प्रतिशत के अनुसार थोड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं तथा बिल्कुल नहीं वाले सूचनादाताओं की संख्या शून्य है।

तालिका क्रमांक 6: अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने सम्बन्धी विचार

क्र0सं0	निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना पसन्द करते हैं	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	21	42
2	नहीं	29	58
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 42 प्रतिशत सूचनादाता अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहते है। 58 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहते है।

तालिका क्रमांक 7: जातीय भेद–भाव होता है।

क्र0सं0	जातीय भेद भाव होता है।	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	26	52
2	नहीं	24	48
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 52 प्रतिशत सूचनादाता मानते हे कि उनके यहां जातीय भेद–भाव होता है। 48 प्रतिशत के अनुसार भेद–भाव नहीं होता है।

तालिका कमांक 8: बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ाने के सम्बन्धी विवरण

क0सं0	बड़े शहरों में पढ़ाना पसन्द करते है	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	38	76
2	नहीं	12	24
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 76 प्रतिशत सूचनादाता अपने बच्चों को बड़े शहरो में पढ़ाना पसन्द करते हे। 24 प्रतिशत सूचनादाता नहीं पढ़ाना चाहते है।

तालिका कमांक 9: अन्य जाति के साथ पढ़ने–लिखने व खान–पान पर प्रतिबन्ध

क0सं0	अन्य के साथ खान–पान पढ़ने लिखने पर प्रतिबन्ध करते है।	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	27	54
2	नहीं	23	46
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 54 प्रतिशत के अनुसार अन्य जातियों के साथ पढ़ने–लिखने तथा खान–पान पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, 46 प्रतिशत कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते है।

तालिका कमांक 10: शिक्षकों के शिक्षण कार्य से संतुष्टि के सम्बन्ध में

क0सं0	शिक्षण कार्य से संतुष्टि	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	08	16
2	थोड़ा बहुत	27	54
3	नही	15	30
4	बिल्कुल नहीं	–	–
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 16 प्रतिशत सूचनादाता शिक्षकों के शिक्षण कार्य से संतुष्ट है। 54 प्रतिशत थोड़ा बहुत संतुष्ट है, 30 प्रतिशत नहीं है तथा बिल्कुल नही का प्रतिशत शून्य है।

निष्कर्ष

सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को अभिभावक दाखिला नही दिलाना चाहते, इसके क्या कारण है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर अभिभावक सरकारी विद्यालयों के शिक्षण कार्य से असन्तुष्ट है। यहां के विद्यालय में शिक्षकों की कमी नही रहती है, शिक्षक विद्यालय में नियमित उपस्थित रहते है, सरकारी विद्यालय का शैक्षिक स्तर अच्छा है उसके बावजूद शिक्षकों का शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्य होने के कारण सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण सही नही है। कई विद्यालयों में संसाधनों का अभाव हैं, बैठने की चटाई , विद्यालयों में पीने का पानी, विद्यालय भवन, तथा शौचालय की सुविधा नही है। विद्यालयों में सभी सुविधाएं लगभग सही स्थिति में उपलब्ध नही है।

अधिकतर अभिभावक बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहते है , बड़े शहरो में पढ़ाना पसन्द करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय भेद–भाव भी एक समस्या है। प्राप्त निष्कषों के आधार पर सुधार हेतु कुछ सुझाव भी दिये गये है।

सुझाव

1. सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अधिकतर अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते है। जिससे वह छात्रों को पूर्ण समय नही दे पाते है। अतः प्राथमिक शिक्षकों को अन्य कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त रखना चाहिए।
2. विद्यालयों में छात्रों को तथा अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए।
3. विद्यालयों में बैठने की, पेयजल, शौचालय तथा विद्यालय भवन, खेल मैदान आदि की सुविधाएं मुख्य रूप से की जानी चाहिए।
4. प्राथमिक विद्यालयों में CBSE प्रणाली के लागू होने से एक ही शिक्षक के ऊपर कई विषयों की जिम्मेदारी बढ़ गयी है। शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिये कक्षा तथा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिये।
5. शिक्षकों की प्रशिक्षणों की अवधि घटा दी जाये जिससे की पढ़न–पाठन कार्य अधिक प्रभावित न हो।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. जहोदा, आर0एन0 त्रिवेदी, रिसर्च मैथ्डोलॉजी'' जयपुर, : कॉलेज बुक डिपो 2010 पृष्ठ संख्या –150।
2. यंग पी0वी0, आर0एन0 त्रिवेदी, ''रिसर्च मैथ्डोलॉजी'',जयपुर, : कॉलेज बुक डिपो, पृ0 सं0–206,207।
3. Rudraprayag District (2011-19 data) https://www.census2011.co.in
4. navbharattimes.indiatimes.com